सीआइटीयू ने नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों की सत्ता को बदलने के लिए संघर्षों में तेजी लाने का आह्वान किया

नयी दिल्ली में 15–17 जुलाई, 2010 को सम्पन्न सीआइटीयू कार्य समिति की बैठक ने श्रमिक वर्ग को आह्वान किया है कि वह मजदूरों की राष्ट्रीय कन्वेंशन के निर्णय के अनुसार आगामी 7 सितम्बर को पूर्ण हड़ताल करके देश में आर्थिक गतिविधियों को ठप्प कर दे। कार्य समिति की बैठक ने सीआइटीयू के उपाध्यक्ष कामरेड एम के पन्धे द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करके मजदूरों की राष्ट्रीय कन्वेंशन के हड़ताल के निर्णय का पूर्ण अनुमोदन किया। कामरेड पन्धे ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार साझा मांगों पर दूसरी ट्रेड यूनियनों के साथ मिल कर इंटक ने देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। उन्होंने इंटक तथा बीएमएस सहित सभी प्रमुख केन्द्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से छेड़े जाने वाले संघर्षों तथा अभियानों की श्रृंखला की रूपरेखा भी पेश की।

दिल्ली में 15–17 जुलाई, 2010 को सम्पन्न कार्य समिति बैठक

उन्होंने कहा कि यद्यपि बीएमएस ने 7 सितम्बर को हड़ताल में शामिल होने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है किन्तु वह पांच सूत्री मांगों पर संयुक्त अखिल भारतीय हड़ताल का समर्थन करेगी और उसके लिए चलाए जाने वाले अभियान का हिस्सा रहेगी।

सीआइटीयू कार्य समिति ने अपनी सभी राज्य समितियों तथा औद्योगिक फैडरेशनों का आह्वान किया है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर बनी ट्रेड यूनियन आंदोलन की इस ऐतिहासिक एकता को कारखानों तथा उद्यमों के स्तर तक लेकर जाएं और यह सुनिश्चित करें कि हड़ताल पूर्ण रूप से सफल रहे।

सीआइटीयू कार्य समिति की यह तीन दिवसीय बैठक सीआइटीयू के मुख्यालय बी टी रणदिवे भवन में सम्पन्न हुई। सीआइटीयू अध्यक्ष कामरेड ए के पद्मनाभन द्वारा सीआइटीयू का लाल झण्डा फहराए जाने के साथ 15 जुलाई की शाम को बैठक शुरू हुई। देश भर से आए कार्य समिति के 127 सदस्यों और आमंत्रितों ने बैठक में भाग लिया।

अध्यक्षीय भाषण

कामरेड ए के पद्मनाभन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि सीआइटीयू के तेरहवें महाधिवेशन के पश्चात् इन चार महीनों के घटना विकास ने महाधिवेशन के इस आंकलन की पुष्टि कर दी है कि जिस आर्थिक रिकवरी की बहुत बात की जा रही है, यह केवल एक मिथ है।

उनका कहना था कि वास्तव में यह संकट बहुत अधिक फैल चुका है और ग्रीस में एक सम्प्रभु ऋण संकट के रूप में विकसित हुआ है और अनेक युरोपीय देशों में इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इन देशों में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के दिशा निदेशों के अनुरूप भारी वेतन कटौतियों, पेन्शन लाभों में कटौती और रिटायरमेंट की आयु में बढ़ोतरी जैसे तथाकथित क्यूरेटिव (रोग निदान) कदमों के माध्यम से मजदूरों की रोजी–रोटी पर हमले किए जा रहे हैं। मजदूर वर्ग की ओर से इन कदमों का भारी प्रतिरोध किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 में हड़ताल की जबरदस्त कार्रवाईयां हुई हैं जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के दसियों लाख मजदूरों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया है और विशेष रूप से स्पेन, पुर्तगाल तथा ग्रीस में ऐसी हड़तालें हुई हैं। लातीनी अमरीका में शक्तिशाली ट्रेड यूनियन संघर्षों के लिए एक नया मंच–"हमारा अमरीका" आंदोलन बना है। इस मंच का निर्माण बुनियादी वर्गीय हितों के पक्ष को मजबूत करने, वर्गीय एकजुटता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रवाद और एक ऐसे रास्ते की खोज को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के साथ किया गया है जो कार्रवाई में एकजुटता की ओर जाता हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि संकट के सघन होने के चलते दुनिया के विभिन्न भागों में वर्गीय

संघर्षों का विकसित होना निश्चित है, यद्यपि उनका स्तर अलग–अलग हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों के घटना विकास के इस दावे को जबरदस्त धक्का लगा है कि पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है।

कामरेड पद्मनाभन ने युरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर विचार विमर्श करने के लिए भारत सरकार की तीखी आलोचना की। यह विचार विमर्श ऐसे समय शुरू किया गया है जब देश में अभी भी एफटीए तथा आसियान समझौतों के नकारात्मक प्रभावों पर विचार विमर्श चल रहा है। युरोपीय संघ की इन मांगों से हमारी कृषि तथा उद्योग को नुकसान पहुंचेगा और इन मांगों से दवा उद्योग तथा दवा की उपलब्धता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनका कहना था कि भारत सरकार भारत की जनता से अधिक, भारतीय तथा विदेशी निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए चिंतित है। कामरेड पद्मनाभन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कार्य समिति को याद दिलाया कि आम आदमी के उन मुद्दों को उठाना सीआइटीयू कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, जो उसके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं। उनका कहना था कि यह सीआइटीयू कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे सरकार की नीतियों को आम आदमी की तकलीफों से जोड़ कर उसकी चेतना को बढ़ाएं। सीआइटीयू अध्यक्ष का यह भी कहना था कि आवश्यकता इस बात की है कि सीआइटीयू और उससे सम्बद्ध ट्रेड यूनियनें जातिगत दमन और युवाओं के जीवन को नियंत्रित करने के लिए खाप पंचायतों के हस्तक्षेप जैसे उन सामाजिक मुद्दों में हस्तक्षेप करें जो जनता के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं।

सीआइटीयू के महासचिव कामरेड तपन सेन ने तेरहवें महाधिवेशन के बाद के राजनीतिक तथा आर्थिक घटना विकास, देश में मजदूर वर्ग की विभिन्न श्रेणियों द्वारा छेड़े गए महत्वपूर्ण संघर्षों पर रिपोर्ट पेश की।

महासचिव की रिपोर्ट

महासचिव की रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया था कि वामपंथ को लगे धक्कों, जिनमें पश्चिम बंगाल में हाल के स्थानीय निकायों के चुनावों में लगा धक्का भी शामिल है, से उत्साहित यूपीए–दो सरकार नियंत्रण हटाने तथा निजीकरण की नीतियों के माध्यम से आक्रामक तथा बौखलाहट भरे कदम उठा रही है। उनका कहना था कि मजदूर वर्ग तथा शोषित–पीड़ित जनता के दरिद्रीकरण और अमीरों के एक छोटे–से तबके द्वारा धन–दौलत बटोरने की प्रक्रिया, जिसे सीआइटीयू के तेरहवें महाधिवेशन ने रेखांकित किया था, अभी भी जारी है।

रिपोर्ट में बताया गया था कि खाद्य सामग्री की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। माल बाजार में सट्टेबाजी खाद्यान्नों तथा दूसरी अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं में जमाखोरी तथा काला बाजारी का अकेला सबसे बड़ा प्रोत्साहनकारी कारक है। परन्तु सरकार सट्टेबाजी पर रोक लगाने से इन्कार करती है। इसके विपरीत वह भारतीय खाद्य निगम को दरकिनार कर नैगम घरानों को खाद्यान्नों की खरीद की अनुमति देने के माध्यम से सट्टेबाजी की इस प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त ही कर रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमिकीकरण से वह इन्कार कर रही है। बिजली और उर्वरक जैसे अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को जिस प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाती है, उसकी कीमतें एक ही झटके में दोगुणी कर दी गई हैं। पैट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल तथा रसोई गैस की कीमतों में हाल ही में की गई भारी बढ़ोतरी पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त करने की दिशा में ही उठाया गया एक कदम है। पिछले चार महीनों की अवधि में पैट्रोल तथा डीजल की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है, जो सरकार की हेकड़ी को ही दिखाती है। इसका उत्तरोत्तर प्रभाव पड़ेगा जिसका परिणाम यह होगा कि महंगाई और बढ़ेगी। तेल की कीमतों की बढ़ोतरी पर सरकार की कपटपूर्ण दलीलों को बेनकाब करते हुए रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि सरकार तेल क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को हाशिए पर डाल कर निजी तेल कम्पनियों को व्यापक स्तर पर प्रवेश दिलाने का मंच तैयार कर रही है।

रिपोर्ट में यह नोट किया गया था कि जनता द्वारा सृजित दौलत के वितरण की व्यवस्था बेहद विकृत है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनोमी (सीएमआइई) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार कारपोरेट सेक्टर की कम्पनियों का सकल मुनाफा वर्ष 2001 में कुल वेज बिल का 44 प्रतिशत था, जो वर्ष 2008 में बढ़ कर 176 प्रतिशत हो गया और यह बढ़ोतरी वैश्विक संकट के बावजूद हुई, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था

पूरी तरह बची हुई नहीं है। इसका अर्थ यही है कि निजी कारपोरेट सेक्टर के मुनाफों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जबकि 50 लाख से अधिक मजदूरों को अपना रोजगार खोना पड़ा है।

रिपोर्ट में अमरीकी साम्राज्यवाद के इशारों पर चलने के लिए यूपीए सरकार की कड़ी आलोचना की गई थी। आसियान देशों के साथ एफटीए, इसी तरह का समझौता युरोपीय यूनियन के साथ करने के लिए जारी बातचीत, मल्टी ब्रांड उत्पादों सहित खुदरा व्यापार में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत और वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करने जैसे जो काम सरकार के एजेंडे पर हैं, वे सभी इस बात का संकेत हैं कि शासक पार्टी भारत की आम जनता के हितों की रक्षा करने की बजाए अमीर औद्योगीकृत देशों की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं की जल्द रिकवरी की राह आसान बनाने के लिए ज्यादा उतावली है।

भोपाल गैस त्रासदी के अनुभव के बावजूद सरकार नाभिकीय जवाबदारी विधेयक संसद में पेश करने पर आमादा है। यह ऐसा विधेयक है जो मुआवजे के उत्तरदायित्व की सीमा तय करता है और सबसे खतरनाक बात यह है कि किसी दुर्घटना की सूरत में किसी भी जिम्मेदारी से अमरीकी नाभिकीय रियक्टर आपूर्तिकर्ता को बचाता है। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा की वामपंथ के नेतृत्व वाली सरकारों की कड़ी वित्तीय सीमाओं के बावजूद उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न जन समर्थक कदमों के लिए बधाई दी गई थी। जहां भारत सरकार की औद्योगिक नीति का केन्द्र निजीकरण है, वहीं केरल की एलडीएफ सरकार ने राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की 12 इकाईयों को पुनर्जीवित किया है और राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में 3 इकाईयां और जोड़ने के लिए कदम उठाए हैं।

महासचिव की रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में माओवादियों तथा तृणमूल कांग्रेस के गिरोहों द्वारा वामपंथ और विशेष रूप से सीआइटीयू तथा सीपीआइ (एम) कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर जारी हमलों की कड़ी निंदा की गई थी और उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी, जिन्होंने इन घृणित हमलों में अपने प्राणों की बलि दी है।

कार्य समिति का यह जोर देकर कहना था कि ये हमले दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियों की साजिशों का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्हें साम्राज्यवादी शक्तियों की शह हासिल है ताकि नव–उदारवाद तथा साम्राज्यवाद परस्त नीतियों के विरोध को कमजोर किया जा सके तथा उसे हाशिए पर डाला जा सके। रिपोर्ट में सीआइटीयू कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया था कि वे माओवादियों के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ें और जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाएं कि कैसे ये ताकतें व्यवहार में नव–उदारवाद तथा वर्तमान व्यवस्था के हित साध रही हैं।

बढ़ता असंतोष

महासचिव की रिपोर्ट का कहना था कि मुख्य विपक्षी दल भाजपा, यूपीए सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों का प्रभावी ढंग से विरोध करने में सक्षम नहीं है क्योंकि जब वह केन्द्र में सत्ता में थी तो उसने भी यही नीतियां लागू की थीं और इतने ही जोर–शोर से लागू की थीं। भाजपा के नेतश्त्व वाली राज्य सरकारें ऐसी ही अमीरपरस्त नीतियां लागू कर रही हैं और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों की ही तरह गहरे भ्रष्टाचार में डूबी हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसके वर्गीय चरित्र के चलते यह स्वाभाविक ही है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जनता के बढ़ते असंतोष का लाभ भाजपा उठाने की कोशिश कर रही है।

कामरेड तपन सेन ने रिपोर्ट में बताया कि भारत के शासक वर्ग देश में दो दलीय शासन प्रणाली का पक्ष लेते हैं जो नव–उदारवादी नीतियों को बिना किसी व्यावधान के जारी रखना सुनिश्चित करती है। यह मजदूर वर्ग के हितों के लिए नुकसान देह है और इसलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ भाजपा अपने साम्प्रदायिक तथा विभाजनकारी एजेंडे को भी आगे बढ़ाना जारी रखे हुए है। मजदूर वर्ग को ऐसी किसी भी कोशिश के खिलाफ सचेत रहना होगा जो उनकी रोजी–रोटी पर हमला करने वाली नीतियों के खिलाफ संघष्र को कमजोर करता हो और उसे विभाजित करता हो।

कार्य समिति ने पहचान की राजनीति के बढ़ते प्रभाव को भी रेखांकित किया। उसने इस जरूरत पर

जोर दिया कि ट्रेड यूनियनों को समाज के सामाजिक रूप से दबे–कुचले तबकों की उचित मांगों तथा आकांक्षाओं को सम्बोधित करना होगा और वर्गीय एकता की रक्षा करनी होगी।

रिपोर्ट में यह कहा गया था कि यूपीए–दो सरकार द्वारा लागू की जा रही नीतियों के खिलाफ उसके सत्ता में आने के बाद के इस साल के दौरान लोगों का असंतोष बढ़ता चला जा रहा है, जो पिछले कुछ महीनों के दौरान वामपंथी दलों और साथ ही साथ केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के नेतृत्व में चलाए गए विभिन्न अभियानों और संघर्षों में जनता की जबरदस्त भागीदारी में प्रतिबिम्बित हुआ है।

रिपोर्ट में बताया गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की अखिल भारतीय फैडरेशन द्वारा की गई आंगनवाड़ी कर्मचारियों की भारी लामबंदी, जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक फैडरेशन द्वारा की गई अभूतपूर्व लामबंदी थी, आशा कार्यकर्ताओं की भारी लामबंदी, सीआइटीयू से सम्बद्ध कोल वर्कर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर कोयला मजदूरों की हड़ताल, विनिवेश के खिलाफ बीएसएनएल कर्मचारियों की हड़ताल, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फैडरेशन का संसद के समक्ष धरना, तमिलनाडु के चेन्नै में हुंडई के मजदूरों का और तिरूनेलवेली में एटीसी टायर मजदूरों का संघर्ष, हिमाचल प्रदेश में पण विद्युत परियोजनाओं के मजदूरों का संघर्ष, पंजाब में बिजली कर्मचारियों का संघर्ष और विभिन्न राज्यों में इसी तरह के दूसरे संघर्ष सभी यही दिखाते हैं कि मजदूर अपने काम तथा जीवन की स्थितियों पर पर हो रहे हमलों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सभी संघर्ष श्रम कानूनों और मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों के खुल्लम खुल्ला उल्लंघन का मुकाबला करते हुए लड़े जा रहे हैं।

महासचिव की रिपोर्ट में बताया गया था कि न्यूनतम वेतन, काम के घण्टों, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा आदि से सम्बन्धित मजदूरों के बुनियादी अधिकारों पर हमला आए दिन की बात हो गई है। और राज्य प्रशासन तथा श्रम विभाग मालिकों के आकाओं की तरह काम कर रहे हैं। मजदूरों की सामूहिक अभिव्यक्ति के किसी भी रूप के प्रति मजदूर ज्यादा ही ज्यादा असहनीय होते जा रहे हैं।

यही है वह स्थिति जिसमें ट्रेड यूनियनों का संयुक्त आंदोलन नए चरण में प्रवेश कर रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना विकास यह है कि आगामी 7 सितम्बर की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान करने में दूसरी ट्रेड यूनियनों के साथ इंटक भी शामिल हुई है। महासचिव की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया था कि मजदूरों तक तमाम मुद्दों को ले जाने के लिए एकदम निचले स्तर तक सीआइटीयू का स्वतंत्र अभियान सर्वोच्च स्तर पर हासिल एकता को मजबूत करने तथा बनाए रखने में मदद करेगा।

महासचिव की रिपोर्ट पर हुई बहस में 41 सदस्यों ने भाग लिया और रिपोर्ट के सूत्रीकरणों तथा प्रस्तावों का पूर्ण अनुमोदन किया।

7 सितम्बर की अखिल भारतीय हड़ताल की पूर्ण सफलता सुनिश्चित करने के तात्कालिक काम के अतिरिक्त कार्य समिति ने कर्मचारी पेन्शन योजना के मुद्दे पर व्यापक अभियान चलाने, सीआइटीयू की स्थापना की चालीसवीं वर्षगांठ मनाने और अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शती मनाने का निर्णय भी लिया। उसने संगठन सम्बन्धी अपने भुबनेश्वर दस्तावेज के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए संगठन पर एक कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय भी भी लिया। सीआइटीयू की राज्य समितियों द्वारा तय किए गए सदस्यता के लक्ष्यों के आधार पर कार्य समिति ने सीआइटीयू की सदस्य संख्या को बढ़ा कर अगले महाधिवेशन तक 84 लाख करने का निर्णय भी लिया।

कामरेड एम के पन्धे ने 16 जुलाई को पी राम मूर्ति ट्रेड यूनियन स्कूल तथा रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। कार्य समिति ने इसके लिए आवश्यक कोष जुटाने और यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि निश्चित समय में इसका निर्माण पूरा हो जाए। इसके साथ ही साथ कार्य समिति ने सीआइटीयू की स्थापना की चालीसवीं वर्षगांठ मनाने के हिस्से के तौर पर विभिन्न स्तरों पर ट्रेड यूनियन कक्षाएं आयोजित करना जारी रखने का भी निर्णय लिया।

मजदूर वर्ग के एकजुट संघर्षों को तेज करने और शोषित–पीड़ित जनता के हितों की रक्षा के लिए सीआइटीयू को मजबूत करने सम्बन्धी सदस्यों की विश्वास तथा जोश की भावना के साथ कार्य समिति की यह बैठक सम्पन्न हुई।

पी राममूर्ति भवन का शिलान्यास

कामरेड एम के पन्धे, पी राममूर्ति भवन का शिलान्यास करते हुए

नयी दिल्ली में 15–17 जुलाई, 2010 को सम्पन्न सीआइटीयू कार्य समिति की बैठक के अवसर पर कामरेड एम के पन्धे द्वारा पी राममूर्ति भवन का शिलान्यास किया गया। 16 जुलाई को आयोजित शानदार समारोह में सीआइटीयू के सभी पदाधिकारियों, कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आए सभी सदस्यों, सीआइटीयू कार्यकर्ताओं की भारी संख्या ने भाग लिया। सीआइटीयू की दिल्ली राज्य समिति की ओर से इसके लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लामबंद किया गया था। शिलान्यास हो जाने के बाद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना के लिए निर्माण कम्पनी तथा आर्कीटैक्ट को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।

कामरेड पन्धे ने समारोह में भाषण करते समय कहा कि कार्यकर्ताओं तथा संगठनकर्ताओं में विचारध ाारक शिक्षा का प्रसार करने के अत्याधिक महत्व है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पूंजीवादी ताकतें मजदूर वर्ग को विचारधारा से शून्य करने की साजिशें कर रही हैं, उन्हें नाकाम बनाने के लिए ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं में विचारधारक शिक्षा का प्रसार जोर शोर से किए जाने की जरूरत है और इस तरह के शिक्षा अभियान लगातार चलाए जाने चाहिएं। यही नहीं, कार्यकर्ताओं और संगठनकर्ताओं में आंदोलन की कार्य नीति, दावपेच एवं समर नीति की समझ पैदा करने और इस मेधा का विकास किए जाने की जरूरत है ताकि वे नित्य प्रतिदिन की ट्रेड यूनियन समस्याओं से निपट सकें और आंदोलन को कारगर तरीके से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने सभी राज्य समितियों से अनुरोध किया कि वे भवन निर्माण के कोष में अपने–अपने कोटे को जल्द से जल्द पूरा करें (प्रति सदस्य 5 रुपए) क्योंकि कानूनी तौर पर हमारे लिए इस भवन का निर्माण हर हालत में सितम्बर 2011 तक पूरा करना जरूरी है। यदि राज्य समितियां अपने कोटे पूरे नहीं करती हैं तो इसके निर्माण कार्य में रुकावट पैदा होगी। सीआइटीयू के अध यक्ष कामरेड ए के पद्मनाभन, महासचिव तपन सेन ने भी इस अवसर पर उपस्थिति को सम्बोधित किया।

याद रहे, सीआइटीयू ने साकेत, नयी दिल्ली में अपने संस्थापक महासचिव तथा लोक ख्यात ट्रेड यूनियन नेता कामरेड पी राममूर्ति की यादगार के रूप में स्थायी रूप से एक ट्रेड यूनियन स्कूल एवं शोध केन्द्र की स्थापना करने का निश्चय किया था। इस भवन में बेसमैंट तथा ग्राउंड फ्लोर के अतिरिक्त तीन और फ्लोर होंगे। इलेक्ट्रिसिटी इम्पलाईज़ फैडरेशन ऑफ इंडिया (ईईएफआइ) तथा आल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फैडरेशन के कार्यालय भी इस भवन में होंगे जिसके लिए दोनों संगठनों की ओर से भवन निर्माण में 25–25 लाख रुपए का योगदान दिया जाएगा। (इस सम्बन्ध में ईईएफआइ की ओर से पहले ही 25 लाख रुपए दिए जा चुके हैं जबकि एआइआरटीडब्ल्यूएफ की ओर से आंशिक भुगतान किया गया है।)